

V. वित्तीय बाजार

2011-12 की तीसरी तिमाही के दौरान वैश्विक वित्तीय बाजारों में दबाव में बढ़ोतरी हुई। बैंक तथा सरकारी ऋण के बीच के प्रतिकूल असर ने समग्र क्षेत्र में संक्रमण जैसी स्थिति पैदा कर दी। दिसंबर 2011 में यूरोपीय यूनियन द्वारा की गई उल्लेखनीय नीतिगत कार्रवाई ने अस्थायी राहत तो दी लेकिन इस कार्रवाई से जनवरी 2012 में यूरो क्षेत्र के नौ देशों के सरकारी ऋण की रेटिंग में की गई कमी को रोका नहीं जा सका। भारतीय वित्तीय बाजार, विशेष रूप से मुद्रा तथा इक्विटी बाजार में वैश्विक घटनाक्रमों तथा कमजोर समष्टि अर्थव्यवस्था के कारण दबाव की स्थिति बनी। डॉलर तथा रुपये की चलनिधि की स्थिति जटिल हो गई परंतु इस संबंध में किए गए उपायों ने दबाव को कम करने में मदद की। घरेलू चलनिधि पर पड़ने वाले दबाव को रिजर्व बैंक द्वारा खुला बाजार परिचालन खरीद के जरिए कम किया गया। पूंजीगत उपायों के जरिए डॉलर के प्रभाव को बढ़ाया गया जिसने सट्टेबाजी को रोकने में मदद की। आगे चल कर बाजारों को संक्रमण की कुछ और घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है।

सरकारी ऋण संकट के चलते वैश्विक वित्तीय बाजारों में दबाव की स्थिति

V.1 2011-12 की पिछली तिमाही के दौरान कमजोर वैश्विक बहाली तथा ऋण की वहनीयता की स्थिति से जुड़ी बढ़ती चिंता, राजकोषीय मितव्ययिता के लक्ष्यों को पूरा करने से जुड़ी चुनौतियां तथा संकटग्रस्त सरकारी ऋण के प्रति यूरोपीय बैंकों के तुलन-पत्रों के भारी एक्सपोजर से जुड़ी घटनाएं वैश्विक वित्तीय बाजार के कार्यकलाप में आसन्न संकट बनकर उभरी हैं। दिसंबर 2011 के दौरान यूरोपीय यूनियन ने महत्वपूर्ण

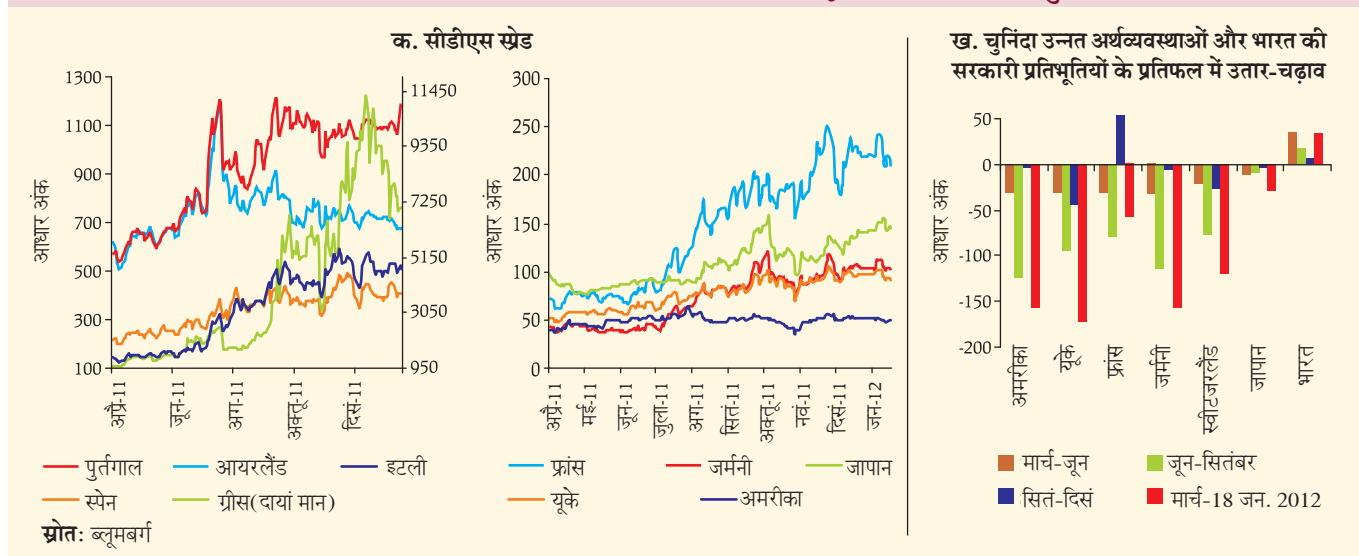
नीतिगत कार्रवाई करके स्थिति का सामना किया, परंतु यूरोपियन फिनांशियल स्टैबिलिटी फंड तथा एसएंडपी द्वारा यूरो क्षेत्र के चार देशों की रेटिंग को दो स्तर कम किए जाने सहित नौ देशों की रेटिंग को डाउनग्रेड किए जाने से दबाव की स्थिति बनी रही। इस पृष्ठभूमि में यूरो क्षेत्र में सरकारी जोखिम के प्रीमियम में तेजी से वृद्धि हुई (चार्ट V.1)। आगे चल कर 2012 में वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव के बने रहने की संभावना है।

बैंक और सरकारी ऋण के बीच सुदृढ़ प्रतिसूचना चक्र की पृष्ठभूमि में बचाव व्यवस्था से अस्थायी राहत मिल सकती है

V.2 वित्तीय संकट से बचने के लिए यूरो क्षेत्र के सरकारों को निजी ऋणों को बचाने के लिए धनराशि की व्यवस्था करनी पड़ी जिससे निजी क्षेत्र के तुलन-पत्रों का असर सरकारी तुलन-पत्र पर भी पड़ा और उसके बाद सरकारी तुलन-पत्रों का असर निजी क्षेत्र के तुलन-पत्रों पर पड़ा। जोखिम प्रीमियम के बढ़ने एवं सरकारी प्रतिभूतियों की आपूर्ति भारी मात्रा में होने से विद्यमान बांड धारकों को हानि उठानी पड़ी। सरकारी गारंटियों के मूल्य में गिरावट आने तथा सरकारी ऋण से जुड़े जोखिमों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता से निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों के तुलन-पत्रों में कमजोरी आई। प्रारंभ में यूरो क्षेत्र के बैंक सीडीएस स्प्रेड में बढ़ोतरी हुई (चार्ट V.2क)। उसके बाद बेलआउट के चलते सरकारी ऋणों के स्प्रेड दबाव में आ गए।

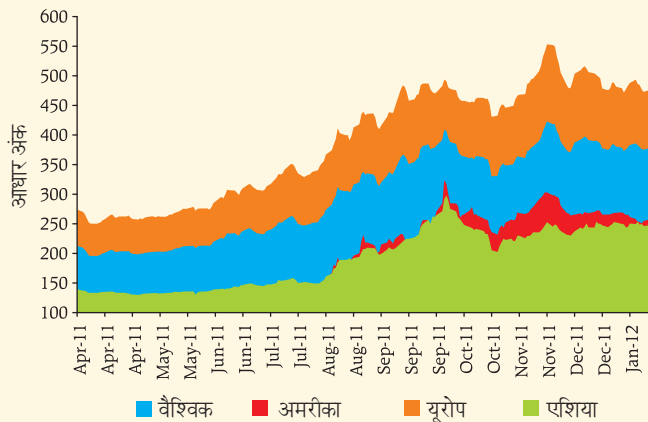
V.3 2011-12 की तीसरी तिमाही में दबाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत कार्रवाई की गई। 26 अक्टूबर 2011 को यूरो क्षेत्र

चार्ट V.1: सरकारी ऋण संकट के संक्रमण जोखिम से वृद्धि की रिकवरी को चुनौती



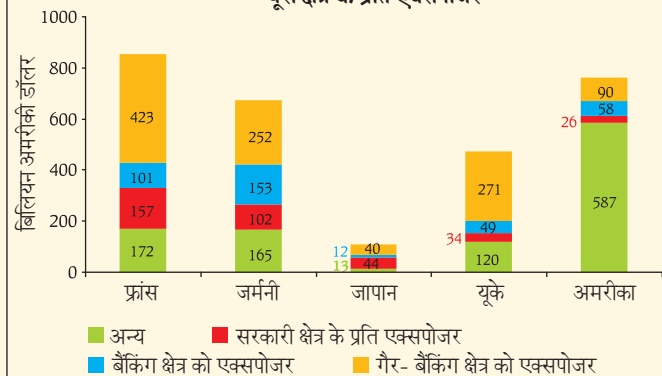
चार्ट V.2: सरकारी जोखिम के प्रति बैंकिंग क्षेत्र का एक्सपोजर

क. विश्व बैंक के सीडीएस के स्प्रेड



स्रोत: ब्लूमबर्ग

ख. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बैंकिंग क्षेत्र का दबावग्रस्त यूरो क्षेत्र के प्रति एक्सपोजर



टिप्पणी : कुल एक्सपोजर में बैंकों के कुल विदेशी ढाँचे और उनके डेरिवेटिव संविदाओं, गारंटियों आदि के माध्यम होने वाले अन्य संभावित एक्सपोजर शामिल हैं। आंकड़े जून 2011 के हैं।

स्रोत : बीआईएस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आरबीआई के स्टाफ का परिकलन।

के नेताओं ने संकट के और फैलने को रोकने के लिए एक समझौता किया जिसमें ये बातें शामिल थीं: (i) बैंक का पुनः पूंजीकरण (लगभग 106 बिलियन यूरो); (ii) बट्टे पर बांड का स्वैच्छिक आधार पर आदान-प्रदान (इसका आशय यह हुआ कि ग्रीस के ऋण के व्यक्तिगत धारकों के लिए 50 प्रतिशत का हेअरकट होगा); तथा (iii) बांड के निर्गम एवं विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) के जरिए 440 बिलियन यूरो के ईएफएसएफ का कोटि उन्नयन जिससे संसाधनों का 4 से 5 गुने लीवरेजिंग करके 1 ट्रिलियन यूरो के हेडलाइन आंकड़े के बराबर किया गया। दिसंबर में यूरो क्षेत्र के देशों ने राजकोषीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एवं आगे और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को 150 बिलियन यूरो के अतिरिक्त निधीयन हेतु पुनः एक समझौता किया। ईसीबी भी सहायता के लिए आगे आया तथा पहले उसने नीति दर में कटौती की तथा यूरो क्षेत्र के 500 से अधिक बैंकों को तीन वर्षीय दीर्घावधि रिपो के एकल परिचालन से 489 बिलियन यूरो का कर्ज उपलब्ध कराया। यूएस फेड, ईसीबी तथा चार अन्य वाणिज्य बैंक अमरीकी डॉलर की स्वैप लाइनों की लागत को आधा करके ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप से 50 आधार अंक ऊपर रखने पर सहमत हुए। 18 जनवरी 2012 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने निधीयन की राशि में 500 बिलियन अमरीकी डॉलर की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव किया।

V.4 इनमें से अधिकांश उपायों ने अस्थायी राहत तो दी परंतु इनसे ऋण संकट का समाधान करने में सफलता नहीं मिली। वर्तमान आकलन यह है कि वित्तीय अस्थिरता बनी रह सकती है क्योंकि ग्रीस के ऋण का हेअरकट उसकी अपेक्षा से अधिक है। ईसीबी द्वारा दी गई अतिरिक्त निधीयन की सुविधा सरकारी ऋण बाजारों तक सुगमता से पहुंच पाने में आशंका है। ऐसी अनिश्चितता की स्थिति में बैंकों तथा सरकारी ऋणों

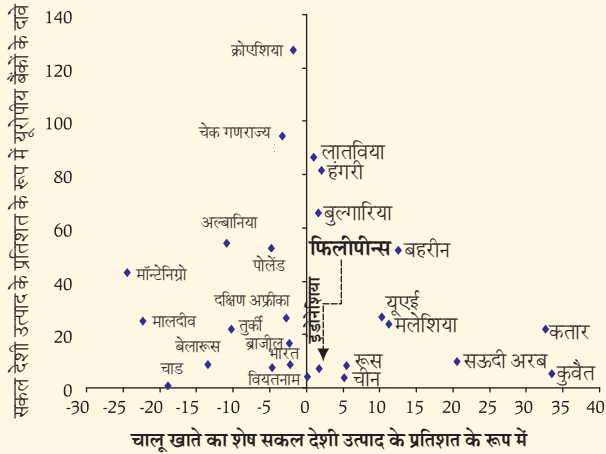
का व्यापक स्तर पर डाउनग्रेड किए जाने से ऋण का वित्तीयन करना अधिक कठिन हो गया है।

यूरो क्षेत्र के संकट का संक्रमण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बैंकिंग क्षेत्र तक फैलने की भारी आशंका है

V.5 यूरोपियन बैंकिंग आथरिटी (ईबीए) द्वारा हाल में किए गए स्ट्रेस टेस्ट से ज्ञात होता है कि अक्टूबर-दिसंबर 2011 के दौरान जर्मनी के बैंकों की पूंजी में कमी का स्तर तीन गुने बढ़कर 13.1 बिलियन यूरो हो गया जबकि यूरोप के बैंकों की पूंजी में कमी का स्तर 106 बिलियन यूरो से बढ़कर 5 बिलियन यूरो हो गया। यूरो के मुख्य क्षेत्रों सहित उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बैंकों का यूरो क्षेत्र की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था (जैसे कि पुर्तगाल, आयरलैंड, इटली, ग्रीस तथा स्पेन) के प्रति भारी मात्रा में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष एक्सपोजर है। यूरो क्षेत्र की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक प्रभावित जर्मनी तथा फ्रांस के बैंक हैं जिसके बाद अमरीका तथा यूके का क्रम है (चार्ट V.2ख)। ऐसे में बैंकिंग चैनलों के जरिए अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण के व्यापक स्तर पर फैलने का जोखिम बढ़ जाता है।

V.6 संकटग्रस्त यूरो क्षेत्र की वित्तीय स्थिति एकाएक बिगड़ने से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बैंकों की स्थिति भी संकट में आ जाएगी जिससे ऋण की उपलब्धता बाधित होगी और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के वास्तविक कार्यकलापों पर इसका भारी प्रतिकूल असर पड़ेगा। अद्यतन सर्वेक्षणों के अनुसार यूरो क्षेत्र के ऋण संकट के गहराने से यूके में बैंकों की ऋण प्रदान करने की क्षमता में कमी आई है। उसी प्रकार यूएस फेड के ऋण अधिकारियों के अद्यतन सर्वेक्षण का निष्कर्ष है कि हाल के महीनों में ऋण की उपलब्धता में कमी आई है।

चार्ट V.3: यूरोपीय बैंकों की डिलीवरेजिंग और उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के चालू खाते की वहीनीयता



स्रोत: बीआईएस और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आरबीआई के स्टाफ का परिकलन।

यूरोपीय बैंकों की डिलीवरेजिंग से उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी का बहिर्वाह बढ़ सकता है

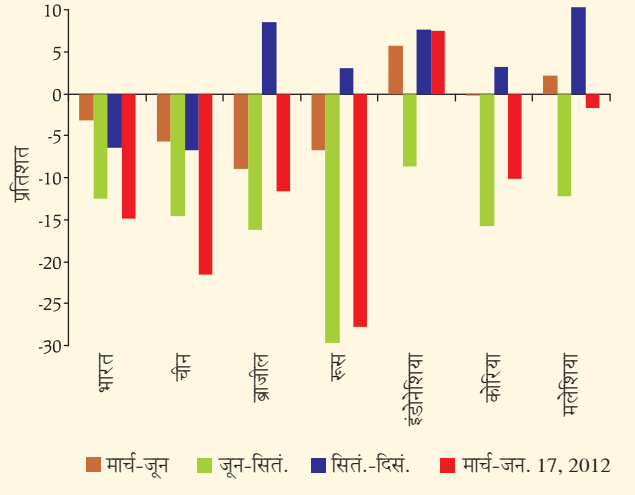
V.7 यूरो क्षेत्र के बैंकों की पूंजी की कमी की बढ़ती चिंता (सरकारी ऋण की समस्याओं के चलते हुए तुलन-पत्र प्रभाव के कारण) से यूरोपीय बैंकों द्वारा डिलीवरेजिंग की शुरुआत की संभावना है और इससे उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उनके कर्ज में कमी आ सकती है। निर्धायन के लिए यूरोपीय बैंकों पर निर्भरता को इन देशों के प्रति जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यूरोपीय बैंकों के ढाँचे से स्पष्ट किया जा सकता है (चार्ट V.3)।

V.8 परंतु उन उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को, जिनका चालू खाते के घाटे के साथ-साथ यूरोपीय बैंकों के प्रति काफी अधिक एक्सपोजर है, तब अपने चालू खाते के घाटे को बनाए रखने में अतिरिक्त समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जब डिलीवरेजिंग के साथ पूंजी का बहिर्वाह भी होने लगेगा। यूरोपीय ढाँचे के प्रति भारत का एक्सपोजर कम है। फिर भी, भारत को भी कर्ज की उपलब्धता, विशेष रूप से व्यापार कर्ज, में कमी तथा उधार की लागत में बढ़ोतरी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

वैश्विक संक्रमण से भारतीय वित्तीय बाजारों में दबाव की स्थिति

V.9 वैश्विक वित्तीय अस्थिरता का भारत पर प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ा, हालांकि विनिमय दर के लचीलेपन के कारण उसका असर सीमित रहा। इक्विटी तथा मुद्रा बाजारों में दबाव की स्थिति रही। भारत मूलतः चालू खाते के घाटे वाला देश है। घाटे का वित्तपोषण पूंजी के अंतर्वाह से किया

चार्ट V.4: उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के इक्विटी बाजार सूचकांक में तिमाही-दर-तिमाही उतार-चढ़ाव



जाता है और अंतर्वाह की राशि सामान्यतः अधिक रहने के साथ-साथ यह स्थिर प्रकार की भी होती है ताकि चालू खाते के घाटे का वित्तपोषण किया जा सके तथा वृद्धि को आगे बढ़ाने में भी मददगार हो। परंतु, वैश्विक बाजार की उथल-पुथल ने जोखिम विमुखता को बढ़ावा दिया और पूंजी के अंतर्वाह में कमी आई जिससे अगस्त-दिसंबर 2011 के दौरान मुद्रा में दबाव की स्थिति बनी जैसी कि जुलाई 2008 से फरवरी 2009 में बनी थी। तथापि जनवरी 2012 में (18 जनवरी 2012 तक) इक्विटी बाजारों तथा विनिमय दर में दिसंबर 2011 के अंत के स्तर से सुधार हुआ जो अन्य कारकों के साथ-साथ मुद्रास्फीति में गिरावट आने के कारण निवल एफआईआई अंतर्वाहों में हुए सुधार की वजह से था।

समष्टि-जोखिम तथा रुपये में गिरावट की वजह से भारतीय इक्विटी बाजारों में दबाव बना

V.10 2011-12 की तीसरी तिमाही में भारतीय इक्विटी की कीमतों में गिरावट जारी रही जो कि बिगड़ती समष्टि आर्थिक परिवेश तथा आय में कम बढ़ोतरी की संभावना से एफआईआई द्वारा निवल बिक्री की वजह से थी (चार्ट V.4)। जोखिम विमुखता के बढ़े हुए स्तर तथा यूरो क्षेत्र के संकट के कारण हुई डिलीवरेजिंग ने 2011-12 की तीसरी तिमाही में भारत सहित उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय बाजारों को प्रभावित किया। एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी में देखी गई ऋणात्मक प्रवृत्ति उभरती तथा विकासशील बाजारों के सूचकांकों के अनुरूप थी। इक्विटी बाजारों में हुए उल्लेखनीय करेक्शन के चलते भारतीय इक्विटी बाजारों का पीई अनुपात मार्च 2011 के अंत के 16.9 से घटकर दिसंबर 2011 के अंत में 16.9 हो गया। परंतु, 2012 में अब तक इक्विटी बाजारों में बेहतरी आई।

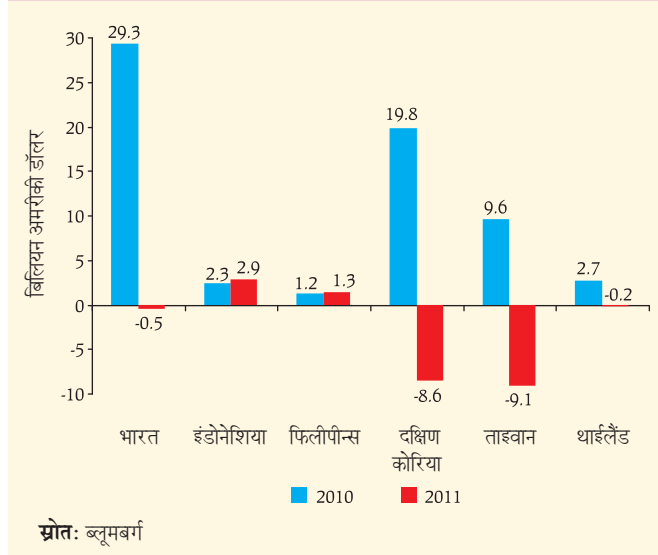
पूंजी अंतर्वाह के कमजोर पड़ने से रुपये के मूल्य में तेज गिरावट आई

V.11 पूंजी के प्रवाह में गिरावट आने के साथ-साथ उच्चतर व्यापार घाटे के कारण अगस्त-दिसंबर 2011 के दौरान भारतीय रुपये की विनिमय दर में तेज गिरावट आई। सट्टेबाजी वाले व्यापार के चलते इस प्रवृत्ति को और बल मिला। 15 दिसंबर 2011 को रुपये का मूल्य एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 54.3 रुपये के सर्वाधिक निचले स्तर तक चले जाने के बाद 20 जनवरी 2012 को सुधरकर 50.3 रुपये तक आ गया। पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के उपायों के असर से स्थिति में सुधार आया। रुपये के मूल्यहास से भारत में पोर्टफोलियो प्रवाह में आई गिरावट तथा इसके कारण वित्तपोषण के लिए उच्चतर चालू खाते के घाटे के स्तर को दर्शाता है (कृपया चार्ट III.2 और V.5 देखें)। ऐसा लगता है कि बाह्य आर्थिक परिवेश संबंधी वर्तमान की ऐसी पृष्ठभूमि में विश्वास के चैनल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उच्च जोखिम समायोजित प्रतिलाभ की दर सहित एफआईआई निवेश की सीमा में की गई बढोतरी ने 2011 के दौरान ऋण खंड में निवल एफआईआई अंतर्वाह को भारी बढ़ावा दिया।

प्राथमिक बाजार से संसाधन जुटाने के स्रोतों में कमी आई

V.12 अक्टूबर-दिसंबर 2011 के दौरान निवेशकों की जोखिम उठाने की कम रुचि को देखते हुए फर्मों ने सार्वजनिक निर्गमों के जरिए संसाधन नहीं जुटाया। शेयर बाजारों के निरंतर ऋणात्मक प्रतिलाभ तथा 2011-12 की पहली छमाही में लिस्टिंग के बाद आईपीओ के ऋणात्मक प्रतिलाभ ने निवेशकों तथा प्रवर्तकों के उत्साह पर प्रतिकूल असर डाला (चार्ट V.6क)। बाह्य क्षेत्र के मामले में, यूरो निर्गमों के जरिए जुटाये गये संसाधन की राशि कम थी क्योंकि यूरो क्षेत्र के ऋण संकट के जारी रहने से यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की स्थिति बिगड़ गई थी।

चार्ट V.5: इक्विटी में पोर्टफोलियो प्रवाह

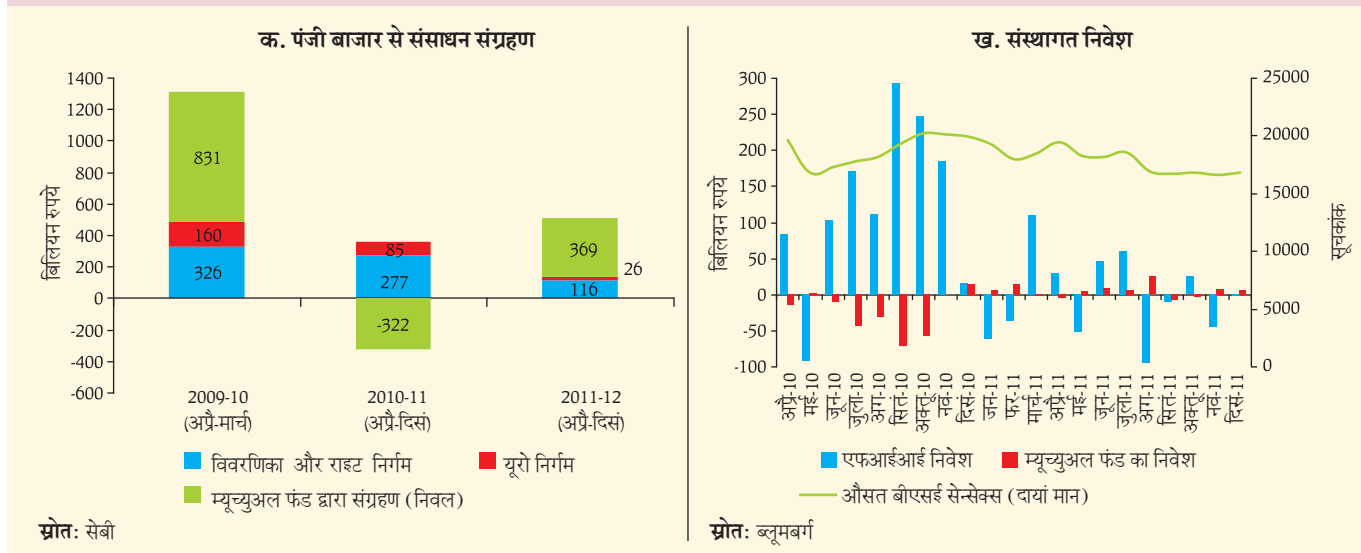


V.13 2011-12 के दौरान (दिसंबर के अंत तक) एफआईआई ने इक्विटी खंड में 43.8 बिलियन रुपये की निवल बिक्री की जबकि म्यूचुअल फंडों ने 42.2 बिलियन रुपये की निवल खरीद की (चार्ट V.6ख)। परंतु, एफआईआई ने जनवरी 2012 में (18 जनवरी 2012 तक) 54 बिलियन रुपये की निवल खरीद की।

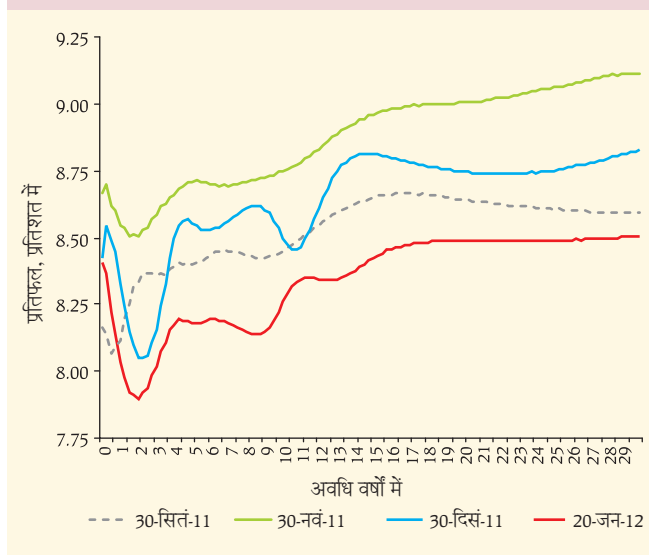
सरकारी उधार अधिक रहने के बावजूद सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में कमी आई

V.14 तीसरी तिमाही के दौरान नवंबर 2011 के मध्य तक सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में भारी सरकारी उधार तथा वर्ष के दौरान राजकोषीय लक्ष्य के पूरे न हो पाने की बाजार की आशंका के चलते

चार्ट V.6: संसाधन संग्रहण और संस्थागत निवेश



चार्ट V.7: सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में उतार-चढ़ाव



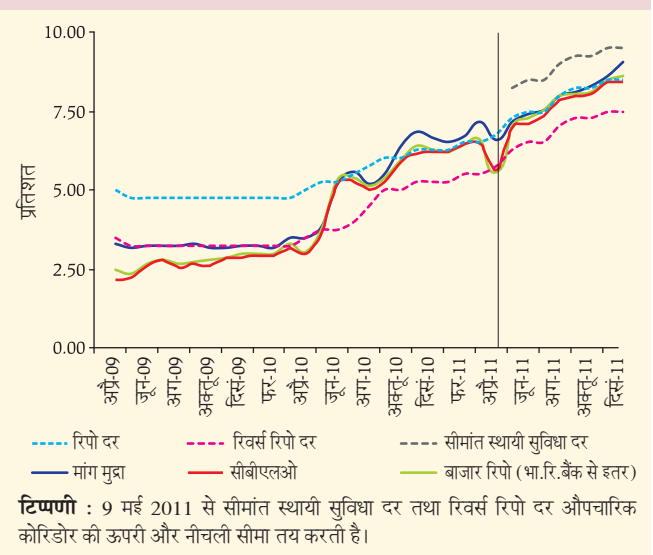
वृद्धि हुई। परंतु, नवंबर 2011 के मध्य से सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में गिरावट आई जो मुख्यतः ऋण में एफआईआई निवेश की सीमा में बढ़ोतरी किए जाने, मौद्रिक कड़ाई में विराम लगाए जाने, मुद्रास्फीति में कमी के लक्षण दिखाई देने तथा खुला बाजार परिचालन की वजह से थी। सरकार द्वारा भारी मात्रा में अतिरिक्त बाजार उधार लिए जाने के बावजूद प्रतिफल में वृद्धि नहीं हुई क्योंकि रिजर्व बैंक ने चलनिधि की प्रणालीगत कमी को ठीक करने के लिए खुला बाजार परिचालन के माध्यम से 719 बिलियन रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों (20 जनवरी 2012 तक) की खरीद कर ली थी (चार्ट V.7)। रिजर्व बैंक के इस आश्वासन से भी बाजार को राहत मिली कि वह आवश्यकतानुसार और खुला बाजार परिचालन करेगा।

ब्याज दरें अपरिवर्तित रहें

V.15 2011-12 की तीसरी तिमाही में ब्याज दरें अपरिवर्तित बनी रहीं जिसकी वजह अक्टूबर में दरों में की गई बढ़ोतरी, भारी मात्रा में सरकारी उधार, चलनिधि की तंग स्थिति तथा ब्याज दरों के विनियमन को समाप्त किया जाना थी। विदेशी मुद्रा तथा इक्विटी बाजारों की तुलना में मुद्रा तथा सरकारी प्रतिभूति बाजार वैश्विक कारकों से कम प्रभावित हुए, परंतु ये मुख्य रूप से घरेलू समष्टि आर्थिक परिवर्तनों से प्रभावित हुए। 2011-12 की तीसरी तिमाही में मुद्रा बाजार की दरें अपेक्षाकृत ऊंची रहीं जो चलनिधि की तंग स्थिति तथा रिजर्व बैंक द्वारा नीति दरों में की गई लगातार वृद्धि को दर्शाती है (चार्ट V.8)।

V.16 दिसंबर 2011 में मुख्यतः अग्रिम करों के कारण हुए बहिर्वाह से चलनिधि की तंग स्थिति की पृष्ठभूमि में मांग दरों में वृद्धि हुई और

चार्ट V.8: मुद्रा बाजार दरें



टिप्पणी : 9 मई 2011 से सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा रिजर्व रिपो दर औपचारिक कोरिडोर की ऊपरी और नीचली सीमा तय करती है।

जिसका औसत 9.04 प्रतिशत रहा। मांग दरों के अनुरूप संपार्श्विकीकृत खंडों (अर्थात् सीबीएलओ तथा बाजार रिपो) की दरों में भी वृद्धि हुई। प्रणाली में चलनिधि के दबाव को कम करने के लिए खुला बाजार परिचालनों के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के अलावा रिजर्व बैंक ने बैंकों को सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत तथा उनकी अतिरिक्त एसएलआर धारिताओं पर 21 दिसंबर 2011 से ओवरनाइट निधि लेने की अनुमति दी।

V.17 नीलामी खजाना बिलों के प्रतिफल में दिसंबर 2011 के मध्य तक वृद्धि हुई जो खजाना बिलों तथा नकदी प्रबंधन बिलों की जारी के जरिए केंद्र द्वारा लिए गए अल्पावधि उधार में हुई भारी वृद्धि तथा अक्टूबर में नीति दरों में की गई बढ़ोतरी की वजह से थी। मौसमी कारणों से चलनिधि की तंगी के बावजूद नीति दर संबंधी मध्य-तिमाही मार्गदर्शन के बाद नीलामी की कट-ऑफ दरों में गिरावट आई।

जमाराशि की दरों में मामूली वृद्धि हुई

V.18 मौद्रिक नीति 2011-12 की दूसरी तिमाही समीक्षा (25 अक्टूबर 2011) में बचत बैंक जमाराशियों की ब्याज दरों पर से नियंत्रण समाप्त किये जाने के बाद छह अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने अब तक अपनी दरों में 100-300 आधार अंकों के दायरे में बढ़ोतरी की है। जिन प्रमुख बैंकों के पास चालू तथा बचत खातों में भारी मात्रा में राशि जमा थी उन बैंकों ने बचत बैंक खातों की ब्याज दरों पर से नियंत्रण समाप्त किये जाने के बाद अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की तथा अद्यतन जानकारी के अनुसार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों तथा पांच विदेशी बैंकों ने 16 दिसंबर 2011 से एनआरई मीयादी जमाराशियों की

सारणी V.1 : जमा और उधार दरें

(प्रतिशत)					
ब्याज दरें	दिसंबर--2010	मार्च -2011	जून -2011	सितं-2011	दिसं-2011
1	2	3	4	5	6
I. देशी जमा दर (1 से 3 वर्ष की अवधि)					
i) सरकारी क्षेत्र के बैंक	7.00-8.50	8.00-9.75	8.25-9.75	8.55-9.75	8.55-9.75
ii) निजी क्षेत्र के बैंक	7.25-9.00	7.75-10.10	8.00-10.50	8.00-10.50	8.00-10.50
iii) विदेशी बैंक	3.50-8.50	3.50-9.10	3.50-10.00	3.50-9.75	3.50-9.75
II. आधार दर					
i) सरकारी क्षेत्र के बैंक	7.60-9.00	8.25-9.50	9.25-10.00	10.00-10.75	10.00-10.75
ii) निजी क्षेत्र के बैंक	7.00-9.00	8.25-10.00	8.50-10.50	9.70-11.00	10.00-11.25
iii) विदेशी बैंक	5.50-9.00	6.25-9.50	6.25-9.50	6.25-10.75	6.25-10.75
III. माध्यिका उधार दर*					
i) सरकारी क्षेत्र के बैंक	8.75-13.50	8.88-14.00	9.50-14.50	10.50-15.25	-
ii) निजी क्षेत्र के बैंक	8.25-14.50	9.00-14.50	9.25-15.00	9.00-15.25	-
iii) विदेशी बैंक	8.00-14.50	7.70-14.05	7.70-14.50	9.13-14.75	-

* : ब्याज दरों का माध्यिका दायरा जिसमें न्यूनतम 60 प्रतिशत कारोबार किया गया। - : उपलब्ध नहीं

ब्याज दर पर से नियंत्रण समाप्त किये जाने के बाद इन जमाराशियों पर उच्चतर प्रतिस्पर्धी दरें दीं। इन बैंकों ने अब तक विभिन्न परिपक्वता वाली अपनी औसत एनआरई मीयादी जमाराशि की दरों में 430-516 आधार अंकों के दायरे में बढ़ोतरी की।

V.19 2011-12 की तीसरी तिमाही में विशेष रूप से निजी क्षेत्र के तथा विदेशी बैंकों ने जमाराशि की ब्याज दरों में 1 वर्ष तक की परिपक्वता के लिए तुलनात्मक दृष्टि से अधिक वृद्धि की। एक वर्ष तक की परिपक्वता के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मोडल जमाराशि दर में 44 आधार अंकों की वृद्धि हुई जबकि 2011-12 की तीसरी तिमाही में मोडल आधार दर 10.75 प्रतिशत पर बनी रही (सारणी V.1)।

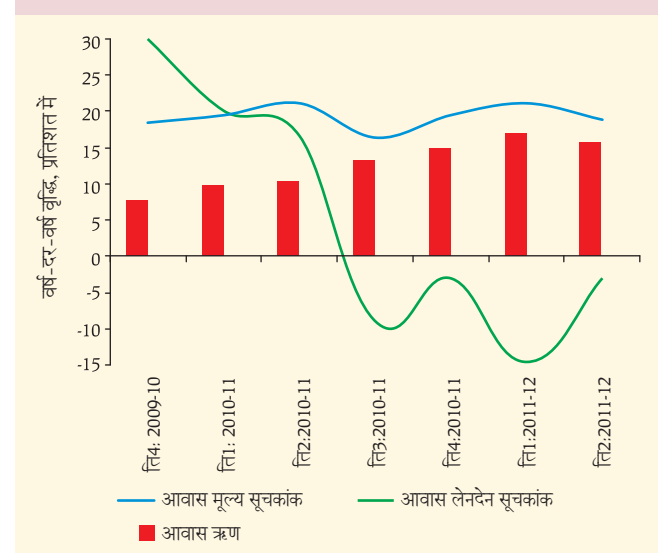
मांग में गिरावट के बावजूद आवास बाजार में कीमतों में बदलाव नहीं दिखा

V.20 समग्र क्रेडिट के उपयोग में गिरावट के बावजूद 2011-12 की दूसरी तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में आवास ऋण में उच्च दर पर बढ़ोतरी होती रही। आवास बाजार में कीमतों में आए ठहराव के साथ-साथ आवास ऋण की उच्चतर मात्रा डेवेलपर्स की मूल्य निर्धारण की शक्ति के बने रहने को दर्शाती है, साथ ही यह आवास के खरीदारों की कमजोर आर्थिक हालत को दर्शाती है। लेनदेनों की कम मात्रा से यह भी संकेत मिलता है कि कई ऐसे परिवार हैं जो कीमतें अधिक होने से आवास बाजार से अलग हो गए हैं (चार्ट V.9)। परंतु 2011-12 की दूसरी तिमाही के आंकड़े अधिकांश शहरों में संपत्तियों की कीमतों में और बढ़ोतरी होने का संकेत देते हैं, हालांकि बढ़ोतरी की दर कम है। साथ ही, पिछली तिमाही के विपरीत लेनदेनों की मात्रा में कुछ बढ़ोतरी हुई। परंतु ये मात्राएं वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कम थीं। संपत्ति बाजारों

में मांग में गिरावट आ रही है परंतु कीमतों में कमी नहीं हुई है जिसका कारण रियल एस्टेट फर्मों द्वारा जमीन पर भारी मात्रा पर कब्जा जमाए रखना तथा मूल्यन की शक्ति को बनाए रखने के लिए नयी परियोजनाओं और बिक्री में कमी किया जाना है।

V.21 संबंधित राज्य सरकारों के पंजीकरण विभागों से संपत्तियों के लेनदेनों के आंकड़ों पर आधारित रिजर्व बैंक के तिमाही आवास मूल्य सूचकांक, जिसमें इस समय 9 शहर शामिल हैं, से सभी शहरों में 2011-12 की दूसरी तिमाही में बेंगलुरु को छोड़कर तिमाही-दर-तिमाही कीमतों में वृद्धि का संकेत मिलता है। दूसरी ओर, इसी अवधि के लेनदेनों के आंकड़े दर्शाते हैं कि मुंबई तथा हाल में सूचकांक में

चार्ट V.9: आवास बाजार



शामिल किये गये कानपुर तथा जयपुर को छोड़कर छह शहरों में लेनदेनों में वृद्धि हुई है।

यदि यूरो क्षेत्र के दबाव में बढ़ोतरी होती है तो वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिम बढ़ सकता है

V.22 आगे चलकर देशी बैंकिंग तथा कारपोरेट क्षेत्रों की निधियन लागत कई घरेलू तथा वैश्विक कारणों से प्रभावित होगी। आर्थिक कार्यकलापों में जारी गिरावट तथा मुद्रास्फीति की अच्छी स्थिति घरेलू निधियन की लागत को कम कर सकती है। यदि यूरो क्षेत्र के दबाव में और वृद्धि होती है तो पूंजी प्रवाह में विपर्यय की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पूंजी पर्याप्तता में मामूली गिरावट तथा हाल की अवधि में कुछ क्षेत्रों में अनर्जक आस्तियों में थोड़ी वृद्धि के बावजूद

भारतीय बैंकों की स्थिति सुदृढ़ बनी हुई है तथा आशा है कि ये यूरो क्षेत्र के संकट के प्रतिकूल असर का सामना करने में सफल होंगे।

V.23 वैश्विक कारकों के अलावा आयात का बढ़ता बिल, निर्यात में वृद्धि की घटती दर, पूंजी प्रवाह को बढ़ाने की दिशा में सुधार हेतु प्रयास की गति तथा घरेलू वृद्धि से जुड़ी चिंताएं ऐसे कारक हैं जो भारतीय वित्तीय बाजारों की गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं। आगे मुद्रास्फीति में गिरावट आने पर नीतिगत प्राथमिकता वृद्धि दर में बहाली की ओर होगी जिसके चलते निवेशकों के विश्वास को प्रोत्साहन मिलेगा और बाजार में उत्साह की बहाली हो सकेगी। फिर भी, यूरो क्षेत्र में नीतिगत बाधाएं, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बहाली की गति तथा उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की गति भारत सहित उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी प्रवाह को प्रभावित करेगी।